



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 1990/फाल्गुन 1, 1911

No. 96] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 1990/PHALGUNA 1, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भाग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1990

का. भा. 162(घ):—केंद्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधि-
नियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा
प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात्
पूर्वांचल बैंक लिमिटेड की बाबत 20 फरवरी, 1990 को कारबार की
समाप्ति से तारीख 20 मई, 1990 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी
है, की कालावधि के लिए अधिस्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन की
कालावधि के दौरान उन बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियों
और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन
रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा
35 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा उसकी
शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय
रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केंद्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड
को पूंजूर की गयी अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, वह बैंक भारतीय
रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना—

(क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई
उधार या अधिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा,
कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संवाय के लिये करार
या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात् उपबंधित
विस्तार और रीति के सिवाय कोई समझौता या ठहराव नहीं
करेगा :—

(1) प्रत्येक बचत बैंक या जालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में
चाहे यह किसी भी नाम से शात हो, कुल अधिशेष के
50 प्रतिशत से घनधिक राशि परन्तु यह तब जबकि
किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के
नाम संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बाबत संवत
रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000
रुपये तथा संस्थाओं के मामले में 25,000 रुपये से अधिक
नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी
निक्षेपकारी संस्था को जो किसी रूप में बैंक का ऋणी है,
संवत नहीं की जाएगी,

- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संवाय आदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसकी अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, अमंदात नहीं है,
- (3) तारीख 20 फरवरी, 1990 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिये प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात् बसूल किए गए बिलों की रकम,
- (4) कोई ऐसा व्यय जो बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए निर्मा वाद या अपील के संबंध में या उक्त बैंक द्वारा अधिस्थापित डिस्को के संबंध में या उसको देये किसी रकम को बसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाता है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या डिस्को या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रुपये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिस्थापन की जायगी।

- (5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहाँ तक वह बैंककारी कंपनी के प्रशासन या संचालन करने के लिए बैंककारी कंपनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहाँ किसी मद पर कुल व्यय अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छः कैलेंडर मास के दौरान उक्त मद के मद्दे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहाँ उक्त अधिधि के दौरान उक्त मद के मद्दे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है और ऐसे में मद पर व्यय 2500 रुपये से अधिक है वहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अधिस्थापन की जायगी।

—(ख) तारीख 20 फरवरी, 1990 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए कारबार के अनुसंग्रह के लिये अपनी स्थावर सम्पत्ति का विपणन अंतरण या उसका अन्वेषण व्यय नहीं करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संवाय, अर्थात् पूर्वांचल बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुपायी या किसी अन्य बैंक द्वारा पूर्वांचल बैंक लिमिटेड की सकारा प्रतिसूतियों या अन्य प्रतिसूतियों के विरुद्ध उधारों/अधियों के या किए गए प्रसिद्ध के लिये आवश्यक है और जो उस तारीख को जिसके अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, अमंदात है अतिरिक्त संवाय कर सकता है।

4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान पूर्वांचल बैंक लिमिटेड पूर्वोक्त संवाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिये अनुज्ञात हो, परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह सम्बन्ध बनाने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिस्थापन नहीं कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किसी बिलों को, जिनकी बसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुबंध पर उस दशा में वापस लौटा सकता यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड ऐसे मास या प्रतिसूतियों को निम्नलिखित रीति में और विस्तार तक

निम्नित या परिपक्व कर सकता जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवर-ड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है, आमातित, अमंदात या संवाय या अन्वेषण प्रसारित किया गया है:—

- (1) किसी ऐसी दशा में जिसमें, अधिस्थगन, उधार देने वाले या उधार देने वालों से देय सभी रकमों के मद्दे पूर्ण संवाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है, और
- (2) किसी अन्य दशा में अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों में जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, नॉने उक्त मास या प्रतिसूतियों पर समाप्तों के अनुपात का कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो।

[सं. 17/7/89-बीबी. ओ. III(ii)]

मन्त्रिपरिषद्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1990

S. O. 162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section hereby makes an order of moratorium in respect of the PURBANCHAL BANK LIMITED for the period from the close of business on the 20th February, 1990 upto and inclusive of the 20th May, 1990 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (B) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the PURBANCHAL BANK LIMITED shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India :—

- (a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :—

- (i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000/- and in the case of institutions Rs. 25,000/- and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way ;
- (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force ;
- (iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 20th February, 1990 and realised before, on or after that date ;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500/- the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred ; and

(v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months proceeding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500/- the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred ;

(b) sell, transfer or other-wise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 20th February, 1990.

3. The Central Government hereby also directs that the PURBANCHAL BANK LIMITED, may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the PURBANCHAL BANK LIMITED by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the PURBANCHAL BANK LIMITED, shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the PURBANCHAL BANK LIMITED.

5. The Central Government hereby further directs that the PURBANCHAL BANK LIMITED may during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the PURBANCHAL BANK LIMITED, may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft :—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally ; and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17/7/89-B.O. III (ii)]
MANTRESHWAR JHA, Jt Secy.

